भारत में ई-गवर्नेंस की स्थिति

समय परिवर्तनशील है। समय के इस बदलते दौर में तकनीकि सुविधाओं की ओर विश्व समुदाय का ध्यान है जिसके कारण विश्व के अधिकांशतः देश ई-गवर्नेंस की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसमें भारत भी ई-गवर्नेंस की दिशा में निरंतर गतिशील है। भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत सन 2000 से ही माना जा रहा है।

ई-गवर्नेंस में ई = इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नेंस = शासन से है। इस प्रकार ई-गवर्नेंस मूल रूप से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (I.C.T) के उपयोग के माध्यम से कार्यों को पूरा करने एवं शासन के परिणाम प्राप्त करने के साथ संबंध है जबकि शासन का सम्बन्ध सभी नागरिकों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा, एक समान रूप से महत्वपूर्ण पहलुओं तथा सार्वजनिक सेवाओं और आर्थिक विकास के लाभ की पहुँच को सभी व्यक्तियों तक सुनिश्चित करने से सम्बन्धित है। विश्व बैंक के अनुसार, ई-गवर्नेंस सरकारी अभिकरणों द्वारा सूचना तकनीकी (wide area network, Internet व Mobile computing) के प्रयोग का सूचक है और यह नागरिकों, व्यापारों और सरकारी अंगों के साथ सम्बन्धों को रूपान्तरित करने की क्षमता रखता है। ई-गवर्नेंस मूल रूप से स्मार्ट शासन की दिशा में एक पहल है जो सरल, नैतिक, उत्तरदायी, अनुक्रियात्मक तथा पारदर्शी शासन का सूचक है।

ई-गवर्नेंस में अन्तःक्रियाओं के चार प्रकार होते हैं- शासन में सरकार की नागरिकों के साथ अन्तर्क्रिया (G-2C), सरकार की सरकार के साथ अन्तर्क्रिया जो कि अन्तर्अभिकरण सम्बन्ध के रूप में होती है। (G-2G), सरकार की व्यापार के साथ अन्तर्क्रिया G2B तथा सरकार की कर्मचारियों के साथ अन्तर्क्रिया (G-2E)।

भारत सरकार ने वर्ष 2000 में इलेक्ट्रॉनिक कार्य सम्पादन प्रक्रिया से सम्बन्धित कानून को क्रियान्वित किया, जिसे I.T act 2000 के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात सरकार ने वर्ष 2003-07 के बीच लागू किए गए ई-गवर्नेंस सम्बन्धित प्लान को मंजूरी दी। इसका मुख्य उद्देश्य ई-गवर्नेंस के लिए एक स्थायी धरातल तैयार करना था। इस दिशा में नवम्बर 2005 में भारत सरकार द्वारा इण्डिया गवर्नमेंट आई एन नामक वेबसाइट की शुरू की। जिसके माध्यम से किसान, विद्यार्थी, व्यवसायी आदि सहित सभी व्यक्ति अपनी काम की सूचना पा सकते हैं। इस वेबसाइट की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रयोक्ता (User) को सर्वप्रथम इस वेबसाइट पर जाकर

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

स्वयं को रजिस्टर कराना होता है। नवम्बर 2010 में ई-गवर्नेंस हेतु खुले मानदण्डों पर एक राष्ट्रीय नीति को अधिसूचित किया गया। यह ई-गवर्नेंस संसाधनों के निरन्तर, मानकीय और सुधारात्मक क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देशों का एक समुच्चय उपलब्ध कराता है। भारत में ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने हेतु कई कदम उठाये गये हैं जो इस प्रकार हैं :-

सरकार की नागरिकों के साथ व सरकार की सरकार के साथ अन्तर्क्रिया के साथ ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में कई कदम उठाये हैं। इनमें भूमि प्रोजेक्ट (कर्नाटक) ज्ञानदूत प्रोजेक्ट (म० प्र०) लोकवाणी प्रोजेक्ट (उ० प्र०) प्रोजेक्ट फ्रेंड्स (केरल) ई-मित्र प्रोजेक्ट्स राजस्थान, ई-सेवा आन्ध्र प्रदेश, स्मार्ट प्रोजेक्ट (आन्ध्र प्रदेश) इत्यादि प्रमुख हैं।

ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं एकीकृत मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में कई पहल किए गए हैं।

मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा किये गए पहलों में ई-कार्यालय, पासपोर्ट इत्यादि प्रमुख हैं। साथ ही इनके साथ ही साथ वीजा और प्रवासन, राष्ट्रीय नागरिक डाटाबेस और यूआईडी परियोजना, पेंशन, बैंकिंग इत्यादि शामिल हैं। राज्य सरकार मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत नगर पालिकाओं में ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई-पंचायत, ई-जिला, राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण प्रोग्राम (N.L.R.M.P), सड़क परिवहन, सम्पत्ति पंजीकरण इत्यादि पहल किए गए हैं। इनके अतिरिक्त एकीकृत मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत किए गए पहलों में ई-प्राक्यूरमेण्ट, ई-न्यायालय, ई-बिज, कॉमन सर्विस सेण्टर (C.S.C) इत्यादि प्रमुख हैं।

इनके अतिरिक्त ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकार द्वारा विगत कुछ महीनों में कदम उठाए गए हैं यथा प्रत्यक्ष नकद हस्तान्तरण, आधार इनेबल्ड पेमेण्ट सिस्टम, डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम, माई गवर्नेंस सिटीजन पोर्टल, ई-क्रान्ति स्कीम, डिजिटल क्लाउड, मोबाइल सेवा इत्यादि प्रमुख हैं।

ई-गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य शासन का विकास और शासन प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। ई-गवर्नेंस से कई प्रकार के लाभ होते हैं। तकनीकि संचार को गतिमान बना देता है जिससे इण्टरनेट, फोन, सेल फोन ने सामान्य संचार में लगने वाले समय को कम कर दिया है। जिससे सूचना तक पहुँच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण होता है।

ई-गवर्नेंस के लाभों में (i) नागरिकों को सरकारी सेवाओं की बेहतर आपूर्ति, (ii) व्यापार और उद्योग के साथ उन्नत अन्तर्क्रियाएँ (iii) अधिक दक्ष सरकारी प्रबंधन (iv) प्रशासन में [illegible] पारदर्शिता में वृद्धि। (vi) प्रक्रिया में लाल फीताशाही

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

और कागजी कार्यवाही में कमी (vii) जवाबदेही व शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर नियोजन एवं समन्वय (viii) सुशासन प्रक्रिया में व्यापक नागरिक भागीदारी इत्यादि।

यद्यपि ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत के समक्ष कई चुनौतियाँ भी है। भारत में अभी तक आबादी का एक बड़ा भाग अशिक्षित है, देश के सभी भागों में अभी तक पूर्णतः बिजली नहीं पहुँच पाई है। इसके अतिरिक्त साक्षरों में भी अधिकांश के पास कम्प्युटर शिक्षा नहीं है। अतः सभी नागरिकों तक ई-गवर्नेंस के लाभ को सुनिश्चित करने हेतु इन चुनौतियों से निपटना होगा इसके अतिरिक्त भारत में साइबर सुरक्षा भी मुद्दा प्रमुख है, क्योंकि वर्तमान समय में हो रहे साइबर हमले को देखते हुए सरकार को साइबर सुरक्षा को बेहतर करने एवं डेटाओं के संग्रह की सुरक्षा को सुनिश्चित करना प्रमुख चुनौती है।

इस प्रकार ई-गवर्नेंस द्वारा प्रशासनिक एवं राजनीतिक जटिलताओं को दूर कर नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। चीन ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत आगे है। वर्तमान में इसने एक APP निकाला है जिसके प्रयोग से स्कैनिंग कर दूरगामी परिणाम ढूँढा जा सकता है, और आवश्यकता की चीजों को भोजन आदि तक पहुँचाया जा सकता है, जिससे पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, उन्मूलन जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि के साथ-साथ शासन संचालन में बेहतर उपलब्धि हासिल कर सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक लाभ की प्राप्ति में सहायक होगा। ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासन में मौजूद लाल फीताशाही को दूर कर नीतियों के क्रियान्वयन में लचीलापन लाकर समाज में समावेशी विकास के बढ़ाने में ई-गवर्नेंस की भूमिका अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस कार्य के लिए देश के नागरिकों को भी प्रशिक्षित होकर सरकार के कार्यों में सहयोग कर ही देश को तरक्की के मार्ग पर पहुँचाया जा सकता है।

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष - राजनीति विज्ञान
डी.के. कालेज, डुमरॉव
दिनांक - 28/05/2020

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA